रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18, 1984/ माघ 29, 1905

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18, 1984/MAGHA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1984

का०आ० 498.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 427 के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों की बाबत या उनके संबंध में प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के, तथा जी०डी०सं० 18, तारीख 30 अक्तूबर, 1983 द्वारा रिपोर्ट की गई आग लगने की घटना और भारतीय दंड संहिता की धारा 427 के अधीन अपराध सं० 147, तारीख 28 नवम्बर, 1983 जो मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) के पुलिस थाना ओबरा में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, की बाबत उन्हीं तथ्यों से उद्भूत होने वाले उसी संव्यवहार के क्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तारित करती है।

[सं० 228/25/83-ए० वी०डी०-II]

हरि कृष्ण वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

ORDER

New Delhi, the 1st February, 1984

S.O. 498.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 5 read with seciton 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under section 427 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and other offences committed in the course of the same transaction in regard to incident of fire reported vide G.D No. 18. dated the 30th October, 1983, and Crime No. 147, dated the 28th November, 1983, under section 427 IPC registered at Police Station Obra, District Mirzapur (Uttar Pradesh).

[No. 228/25/83-AVD-II]

H. K. VERMA, Under Secy.

भारतीय रिज़र्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, 13 जनवरी, 1984

का. आ. 499 :—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) के अंतर्गत गठित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 11 नवम्बर 1985 तक की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1-क) के उपबन्धों से छूट देता है ।

[संदर्भ आरपीसीडी सं. 1718/324-84]

ति.ना. अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Department)

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 13th January, 1984

S.O. 499.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby exempts all Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) from the provisions of sub-section (1A) of Section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 for a period upto November 11, 1985.

[Ref. RPCD. No. 1718/324-84]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1984

आय-कर

का० आ० 500.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त विभाग की दिनांक 4-6-83 की अधिसूचना संख्या 5255 (फा० सं० 398/18/83-आ०क०ब०) का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जानकी रमन को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री जानकी रमन द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 5601 (फा०सं० 398/18/83-आ०क०ब०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st January, 1984

INCOME TAX

S.O. 500.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5255 (F. No. 398/18/83-ITB) dated 4th June, 1983, the Central Government hereby authorises Shri S. Janakiraman, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. Janakiraman takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5601/F. No. 398/18/83-IT(B)]

आय-कर

का० आ० 501.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० संथालिंगम को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एन० संथालिंगम द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 5603/फा० सं० 398/18/83-आ०क०ब०]

INCOME TAX

S.O. 501.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri N. Santhalingam being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification comes into force with effect from the date Shri N. Santhalingam takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5603/F. No. 398/18/83-IT(B)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1984

आय-कर

का० आ० 502.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 27-7-83 की अधिसूचना संख्या 5342 (फा०सं० 398/7/83-आ०क०ब०) का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० पी० मेहतो को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री आर० पी० मेहतो द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[संख्या 5606/फा०सं० 398/3/84-आ०क०ब०]

बी०ई० अलेक्जैन्डर, अवर सचिव

New Delhi, the 1st February, 1984

INCOME TAX

S.O. 502.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5342 (F. No. 398/7/83-IT(B), dated 27th July, 1983, the Government hereby authorises Shri R. P. Mehto, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri R. P. Mehto takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5606/F. No. 398/3/84-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1984

(आय-कर)

का०आ० 503.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्री प्रसन्न वीर अंजनेया स्वामी मंदिर, बगलौर" को समस्त कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० 5598 (फा०सं० 176/77/82-आ.क.नि.-I)]

आर० के० तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd January, 1984

INCOME-TAX

S.O. 503.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Prasanna Veeranjaneya Swamy Temple, Bangalore" to be a place of public worship of renown throughout the State of Karnataka.

[No. 5598/F. No. 176/77/82-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1984

आदेश

स्टाम्प

का०आ० 504.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैं० बालारपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बालारपुर को केवल एक लाख 50 हजार रुपये के समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त कम्पनी द्वारा दो करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों के रूप में, जारी किए जाने वाले बन्धपत्रों पर प्रभार्य है ।

[सं० 8/84-स्टाम्प-फा०सं० 33/4/84-वि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 1984

ORDER

STAMPS

S.O. 504.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Ballarpur Industries Ltd., Ballarpur to pay consolidated stamp duty of rupees One Lakh and Fifty thousands only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of rupees Two Crores to be issued by the said Company.

[No. 8/84-Stamps-F. No. 33/4/84-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1984

आयकर

का० आ० 505.—इस कार्यालय की दिनांक 27-12-80 की अधिसूचना सं० 3778 (फा०सं० 203/287/80-आ० क०नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि भास्कराचार्य प्रतिष्ठान पूना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देन दारियां दर्शाते हुए तुलना पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पूना

यह अधिसूचना 24-9-1983 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 5608(फा० सं० 203/248/83-आ०क०नि०-II)]

मदन गोपाल चन्द गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd February, 1984

INCOME TAX

S.O. 505.—In continuation of this Office Notification No. 3778 (F. No. 203/287/80-ITA. II) dated 27th December, 1980, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :

(i) That the Bhaskaracharya Pratishthana, Poona will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

BHASKARACHARYA PRATISHTHANA, POONA

This notification is effective for period from 24th September, 1983 to 31st March, 1986.

[No. 5608 (F. No. 203/248/83 ITA.II)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

का० आ० 506.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 34 के साथ पठित नियम 24 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अधिसूचना सं० का नि०आ० 639 तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(1) भाग-I में साधारण केन्द्रीय सेवा-समूह "ख" के सम्बन्ध में,—

(क) स्तम्भ 1 में शीर्षक "नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ सभी लेखा तथा लेखापरीक्षा कार्यालयों, के अन्तर्गत, "लेखापरीक्षा अधिकारी" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी" ;

(ख) स्तम्भ 1 में शीर्षक "भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा स्टाफ कालेज के अन्तर्गत "लेखा अधिकारी" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी";

(2) भाग-II में साधारण केन्द्रीय सेवा—समूह "ग" से सम्बन्धित स्तम्भ 1 में शीर्षक "भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा का कार्यालय" और "नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ सभी लेखा और लेखापरीक्षा कार्यालय" के अन्तर्गत, "अधीनस्थ लेखा सेवा",

"अधीनस्थ रेलवे लेखापरीक्षा सेवा" (अर्थात् अनुभाग अधिकारी) शब्द, कोष्ठक और अक्षर दोनों स्थानों पर, जहां भी आते हैं, उनके स्थान में निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे अर्थात् :—

"अनुभाग अधिकारी सेवा"

2. मद सं० (1) द्वारा अनुसूची के भाग-I में किया गया संशोधन 1 मार्च 1984 से प्रभावी होगा।

[फा०सं० सी०-11021/1/84-ई०जी०I]

के० एल० मेहता, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं० का०नि०आ० 639 तारीख 28-2-1957 की अनुसूची का०आ० 4049 दिनांक 10-12-1979 द्वारा पहले प्रतिस्थापित की गई थी, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22-12-79 के भाग-II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी।

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 6th February, 1984

S.O. 506.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.R.O. 639 dated the 28th, February, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(i) in part-I relating to General Central Service—Group 'B',—

(a) under the heading "All Accounts and Audit Offices subordinate to the Comtroller and Auditor General", in column 1, after the entry 'Audit Officer", the following entry shall be inserted, namely :—

"Assistant Audit Officer";

(b) under the heading "Indian Audit and Accounts Service Staff College", in column 1, after the entry "Accounts Officer", the following entry shall be inserted, namely :—

"Assistant Audit Officer";

(ii) in Part II relating to General Central Service, Group 'C' under the heading "Office of the Comptroller and Auditor General of India" and "All Accounts and Audit Offices subordinate to the Comptroller and Auditor General", in column 1, for the words, bracket, and letters, 'Subordinate Accounts Service, Subordinate Railway Audit Service (i.e. Section Officer)" at both the places where they occur, the following words shall be substituted, namely :—

"Section Officers' Service"

2. The amendment made in Part I of the Schedule by item (i) shall come into force on the Ist March, 1984.

[F. No. C. 11021/1/84-EGII]

K. L. MEHTA, Under Secy.

Note :—The Schedule to the original notification S.R.O. 639 dated 28-2-1957 was last substituted by S.O 4049 dated 10-12-1979, published in the Gazette of India dated 22-12 1979 in Part II, Section 3, sub-section (ii).

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1984

का०आ० 507.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री दिनकर राव को प्रथमा बैंक, मुरादाबाद का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-1-1984 से प्रारम्भ होकर 30-6 1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री दिनकर राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 2-5/82-आर.आर.बी.)

एस०एस० हसूरकर, उप सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 27th January, 1984

S.O. 507.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Dinkar Rao as the Chairman of Prathma Bank, Moradabad and specifies the period commencing on the 1-1-1984 and ending with the 30-6-1985 as the period for which the said Shri Dinkar Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-5/82-RRB]

S. S. HASURKAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1984

का०आ० 508:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री बी० बी० मोनालकर को 2 जनवरी, 1984 से आरम्भ होने वाली और 1 जनवरी, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/39/83-बी०ओ०-I-(1)]

New Delhi, the 31st January, 1984

S.O. 508.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri B. V. Sonalkar, as the Chairman and Managing Director of the Central Bank of India for a period commencing on January 2, 1984 and ending with January 1, 1987.

[No. F. 9|39|83-BO.I(1)]

का० आ० 509 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री बी०बी० मोनालकर को, जिन्हें 2 जनवरी, 1984 से सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/39/83-बी० ओ०I(2)]

च० वा० मीरचन्दानी, उप सचिव

S.O. 509.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B. V. Sonalkar, who has been re-appointed as Managing Director of the Central Bank of India with effect from January 2, 1984 to be the Chairman of the Board of Directors of the Central Bank of India with effect from the same date.

[No. F 9|39|83-BO I(2)]

C. W. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

अधिसूचना सं० 4/83

गुन्टूर, 12 दिसंबर, 1983

का० आ० 510:—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा अपनी शक्तियाँ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 173-पी० पी० (5) तथा 173-पी० पी० पी० (6) के अन्तर्गत सहायक समाहर्ताओं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को प्रत्यायोजित करता हूं ।

[फाइल सं० 4/16/10/83-एम० पी० 2 (पी एफ)]

सुकुमार शंकर, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 4/83

Guntur, the 12th December, 1983

S.O. 510.—In exercise of powers vested in me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I hereby delegate the powers vested in me under the Rules 173-PP(5) and 173-PPP(6) of Central Excise Rules, 1944 to the Assistant Collectors of Central Excise.

[File No. IV/16/10/83-M.P.2(PF)]

SUKUMAR SHANKAR, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1984

का० आ० 511 :—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा मैसर्स हैबलेस पेस्ट केन्ट्रोल सर्विसिज, 53, डी० बी० बन्दोकर मार्ग, पोस्ट बाक्स नं० 283, कैम्पल, पानाजी, गोआ को एल्यूमीनियम फासफाइड का निम्नलिखित मदों के लिए धूमक के रूप में प्रयोग करते हुए धूमीकरण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है :—

1. तेल रहित चावल की भूसी; और
2. पिसी हुई हड्डियाँ, खुर और सींग ,

[मिसिल सं० 5/1/84-ईआईएण्डईपी]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th February, 1984

S.O. 511.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of one year M/s. Hebble's Pest Control Services, 53, D. B. Bandokar Marg, P.B. No. 283, Campal, Panji Goa, as an agency for the fumigation, using Aluminium Phosphide as a fumigant for the following items :—

1. De-oiled Rice Bran; and
2. Crushed Bones, Hooves and Horns.

[F. No. 5/1/84-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1984

का० आ० 512 :—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, जैद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री के०के० नारंग को तत्काल से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० टी० 4330/2/84]

बी० एस० निडर, अवर सचिव (कौंसलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st January, 1984

S.O. 512.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri K. K. Narang, Assistant in the Embassy of India, Jeddah to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T. 4330/2/84]

B. S. NIDDAR, Under Secy. (Gen.)

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 2 जनवरी, 1984

का० आ० 513:—परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 (सन् 1962 का 33 वां), की धारा 16, 17 और 23 के अन्तर्गत बनाए गए कुछ नियामक तथा सुरक्षा कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए इस विभाग के तारीख 15 नवम्बर, 1983 के आदेश संख्या 25/2/83-ई आर के अधीन बनाये गए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1.	प्रोफैसर ए० के० डे, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, पवाई, बम्बई।	अध्यक्ष
2.	डा० ई० सी० सुब्बा राव निदेशक, टाटा अनुसंधान विकास तथा अभिकल्पन केन्द्र, पुणे।	सदस्य
3.	प्रोफैसर वी० डी० गुप्ता, प्रोफैसर तथा अध्यक्ष, विकिरण चिकित्सा विभाग, स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	सदस्य
4.	श्री वी० एन० मेकोनी, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग सुरक्षा पुनरीक्षा समिति परमाणु ऊर्जा विभाग।	सदस्य
5.	श्री पी० एन० कृष्णामूर्ति, रीवैज्ञानिक अधिकारी (एच)	सदस्य-सचिव

[सं० 25/2/83 ईआर]

एस० के० भंडारकर, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 2nd January, 1984

S.O. 513.—The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) constituted under this Department's Order No. 25|2|83-ER dated November 15, 1983 to carry out certain regulatory and safety functions envisaged under section 16, 17 and 23 of the Atomic Energy Act 1962 (33 of 1962) will consist of the following members:

(1) Prof. A. K. De,
Director,
Indian Institute of Technology,
Powai, Bombay. —Chairman

(2) Dr. E. C. Subba Rao,
Director,
Tata Research Development and
Design Centre, Pune. —Member

(3) Prof. B. D. Gupta,
Professor & Chairman,
Department of Radiotherapy,
Post Graduate Institute of
Research,
Chandigarh. —Member

(4) Shri V. N. Meckoni,
Chairman,
DAE Safety Review Committee,
Department of Atomic Energy. —Member

(5) Shri P. N. Krishnamoorthy,
Scientific Officer (H). —Member-Secy.

[No. 25|2|83-ER]

S. K. BHANDARKAR, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1984

का० आ० 514 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० सोकासन 44/26 से जी जी एस सोकासन तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 4-10-80 से समाप्त कर दिया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

सोकासन 44/26 से जी जी एस सोकासन II तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	जगुदण	3290	18-9-82	4-10-80

[सं० 12016/62/80-प्रोड० II]

MINISTRY OF ENERGY

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 30th January, 1984

S. O. 514—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Sob 44/26 to Ggs Sob II in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on————————

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of pipeline from D. S. Sob 44/26 to Ggs Sob II

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy, Deptt. of Petroleum.	Jagudan	3290	18-9-82	4-10-80

[No. 12016/62/80-Prod-II]

का० आ० 515 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० 2 सोकासन से जी० जी० एस II सोकासन तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 20-2-81 से समाप्त कर दिया है ।

अत: अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

2 सोकामत से जी जी एस II सोकामत तक पाइप लाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	जगुदण	1913	23-4-83	20-2-81

[सं० 12016/26/81-प्रोड]

ह०/-गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 515.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. 2 Sob. to Ggs II Sob. in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 20-2-81.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of pipeline from D.S. 2 Sob to Ggs II Sob.

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy, Deptt. of Petroleum.	Jagudan	1913	23-4-83	20-2-81

[No. 12016/26/81-Prod.]

Sd/- Competent Authority Under The Act For Gujarat

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1984

का०आ० 516:—यत: भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उप धारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा 1 के खंड (क) के अनुसरण में और पंजाब सरकार से परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार ने डा० के०एस० अहलूवालिया को डा० (श्रीमती) लीला राम कुमार के स्थान पर 21 सितम्बर, 1983 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस०आ० 138 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (क) के अधीन मनोनीत" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :

"11. डा०के०एस० आहलूवालिया, निदेशक, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा पंजाब"

[संख्या वी० 11013/3/81-एम०ई० (पी)]

प्रकाश चन्द्र जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 17th January, 1984

S.O. 516.—Whereas the Central Government is pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the Government of Punjab have nominated Dr. K. S. Ahluwalia, Director, Research and Medical Education, Punjab to be a member of the Medical Council of India Vice Dr. (Mrs) Leila Ram Kumar, with effect from the 21st September, 1983.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Govt. hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January 1960, namely:—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3", for serial number 11 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted namely:—

"11. Dr. K. S. Ahluwalia,
Director, Research and Medical Education,
Punjab."

[No. V. 11013/3/81-M.E.(P)]

P. C. JAIN, Under Secy.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(नागरिक पूर्ति विभाग)
भारतीय मानक संस्था
नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1984

का०आ० 517.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस सं० सीएम/एल-0717560 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं लाइसेंसधारी के अपने अनुरोध पर 1983-03-10 से रद्द किया गया है :

अनुसूची

लाइसेंस सं० और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
सीएम/एल-0717560 1978-08-21	मैसर्स कोहिनूर रबड़ वर्क्स प्रा० लि०, 35/1 ए कैनाल पूर्व रोड, कलकत्ता-700011 (प० बंगाल)	रबड़ के सन्निवेश जोड़, टाइप बी, ग्रेड 1	IS : 368—1979 रबड़ की चद्दरों के जोड़ और रबड़ के सन्निवेश जोड़ की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[सीएमडी/55 : 0717560]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Civil Supplies)
INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 23rd January, 1984

S.O. 517.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-0717560 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1983-03-10 at the request of the licensee.

SCHEDULE

Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/Process Covered by the licence Cancelled	Relevant Indian Standards
CM/L-0717560 1978-08-21	M/s. Kohinoor Rubber Works (Pvt) Ltd., 35/1A, Canal East Road, Calcutta-700 011 (West Bengal).	Rubber insertion jointing, Type B, Grade 1	IS : 368—1979 Specification for sheet rubber jointing and rubber insertion jointing (second revision).

[CMD/55 : 0717560]

का०आ० 518.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस सं० सीएम/एल-0854560 जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं लाइसेंसधारी के अपने अनुरोध पर 1983-02-15 से रद्द किया गया है।

अनुसूची

लाइसेंस सं० और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
सीएम/एल-0854560 1980-03-31	मैसर्स एबको लि०, डा० बी०सी०राय एवेन्यू, दुर्गापुर (प० बंगाल) इनका कार्यालय : 4ए रायड स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 प० बंगाल में है।	आबद्ध खनिज ऊन, गुण 1, 2, 3 और 4	IS : 8183—1976 आबद्ध खनिज ऊन की विशिष्टि

[सीएमडी/55 : 0854560]
ए० एस० चीमा, अपर महानिदेशक

S.O. 518.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that the licence No. CM/L-0854560 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1983-02-15 at the request of the licensee:—

SCHEDULE

Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/Process Covered	Relevant Indian Standards
CM/L-0854560 1980-03-31	M/s. PIBCO Ltd, Dr. B.C. Roy Avenue, Durgapur (West Bengal) having their office at 4A Royd Street, Calcutta-700 016. (West Bengal)	Bonded mineral wool, groups I, II, III & IV	IS : 8183—1976 Specification for bounded mineral wool

[CMD/55 : 0854560]

A. S. CHEEMA, Addl. Director General

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी 1984

का०आ० 519.—भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पाद बोर्ड के अध्यक्ष, श्री आर०सी० मिश्र को तत्काल तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक अथवा वर्तमान पद छोड़ने तक, भी पहले हो, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है।

[ए वी 24012/1/83-ए ए/एफ-II]

एस०सी० कोहली, वित्त नियंत्रक

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 27th January, 1984

S.O. 519.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoint Shri R. C. Misra, Chairman, Central Board of Excise and Customs as a part-time Member of the International Airports Authority of India with immediate effect for a period of three years or till his date of superannuation or relinquishing of present office, whichever is earlier.

[AV. 24012/1/83-AA/F.II]

S. C. KOHLI, Financial Controller

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1984

का० आ० 520.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बी० आर० रेड्डी के स्थान पर श्री ए० कमलशेकरन को मद्रास डाक श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 3757, तारीख 29 अक्तूबर, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "डाक कर्मकारों और नौवहन कंपनियों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अधीन क्रम सं० (2) के स्थान पर "श्री कमलशेकरन" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा० सं० एल० डी० एम०/6/82-यू० एस० (एस०)-II]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 2nd February, 1984

S.O. 520.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso of sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri A. Kamalasekaran as a member of the Madras Dock Labour Board vice Shri V. R. Reddy and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 3757 dated the 29th October, 1982, namely :—

In the said notification under the heading "Members representing Employers of Dock Workers and Shipping Companies" for the entry against Serial No. (2) the entry "Shri A. Kamalasekaran" shall be substituted.

[F. No. LDM/6/82-US(L)-II]

का० आ० 521:—श्री बी० आर० रेड्डी ने जिन्हें भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 3757, तारीख 29

अक्तूबर, 1982 द्वारा मद्रास डाक श्रम बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उक्त डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में अपना पद त्याग करने की इच्छा व्यक्त की है,

और इस प्रकार उक्त डाक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हो गई है ;

अत. अब, केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में, उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा० सं० एल० डी० एम०/6/82-यू० एस० (एल०)-I]
वी० शंकरलिंगम, उप सचिव

S.O. 521.—Whereas Shri V. R. Reddy who was appointed as a member of the Madras Dock Labour Board by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 3757 dated the 29th October, 1982 has expressed his desire to relinquish his position as a member of the said Dock Labour Board ;

And whereas a vacancy has thus occurred in the said Dock Labour Board ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDM/6/82-US(L)-I]
V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1984

का० आ० 522.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 8 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित और व्यक्तियों को अगले आदेश तक, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से परामर्श करने के बाद, उक्त बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त करती है ।

तमिल

1. श्री आर० संपत
2. श्रीमती लीला नरेन्द्रन
3. श्रीमती बी० शांता
4. श्रीमती विमला वासुदेव राव
5. श्रीमती हरिप्रिया रामभद्रन
6. श्री एच० एस० एस० लारेंस
7. श्रीमती रानी गणेशन
8. श्री ज यभारती
9. श्री एस० काडस्वामी
10. डा० (श्रीमती) एस० सुलोचना
11. श्री एस० मुथिया

तेलुगु

12. डा० एस० अक्की रेड्डी
13. श्रीमती सी० धनलक्ष्मी
14. श्रीमती इवातुरी बालाराव
15. श्रीमती राजलक्ष्मी संकावल्ली
16. श्री टी. सुब्बा रामी रेड्डी

मलयालम

17. श्रीमती रमणी बालाशंकर
18. डा० के० ए० कलावती
19. श्री के० एम० प्रभाकर वरिआर
20. कुमारी सरस्वती मेनन
21. श्रीमती गीता कृष्णनकुट्टी
22. श्रीमती मिनी कृष्णन
23. डा० के० सी० पद्मावती
24. श्रीमती निर्मला रामचन्द्रन
25. श्री वी० जोसफ जार्ज
26. डा० सी० जी० राजेन्द्र बाबू

हिन्दी

27. श्री आर० गौरी राजन
28. श्रीमती नीरा एस० कुमार
29. श्रीमती मीनू राठौर
30. श्रीमती जहांआरा हुसैन
31. श्रीमती जुबेदा असगरअली

[फाइल संख्या 811/1/83-एफ० (सी०)]
के० एस० वेंकटरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st February, 1984

S.O. 522.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule (7) read with sub-rules (1) and (2) of rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby appoints the following more persons after consultation with the Board of Film Certification, as Members of the Advisory Penal of the said Board at Madras with immediate effect until further orders :—

Tamil

1. Shri R. Sampath
2. Smt. Leela Narendran
3. Smt. B. Shantha
4. Smt. Vimala Vasudeva Rao
5. Smt. Haripriya Ramabhadran
6. Shri H. S. S. Lawrence
7. Smt. Rani Ganeshan
8. Shri Jayabharathy
9. Shri S. Kandaswamy
10. Dr. (Mrs.) S. Sulochana
11. Shri S. Muthiah

Telugu

12. Dr. S. Akki Reddy
13. Smt. C. Dhanalakshmi

14. Smt. Ivatury Bala Rao
15. Smt. Rajalakshmi Sunkavally
16. Shri T. Subba Rami Reddy

Malayalam

17. Smt. Ramani Balashankar
18. Dr. K. A. Kalavathi
19. Shri K. M. Prabhakara Variar
20. Miss Saraswathy Menon
21. Smt. Gita Krishnankutty
22. Smt. Mini Krishnan
23. Dr. K. C. Padmavathi
24. Smt. Nirmala Ramachandran
25. Shri V. Joseph George
26. Dr. C. G. Rajendra Babu

Hindi

27. Shri R. Sowri Rajan
28. Smt. Nira S. Kumar
29. Smt. Minu Rathor
30. Smt. Jahanara Hussain
31. Smt. Zubeida Asgarali

[File No. 811/1/83-F(C)]

K. S. VENKATARAMAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1984

का०आ० 523.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के विभिन्न अनुमंडलों के सभी अनुमंडलाधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिए उड़ीसा राज्य में मुआवजा पूल की भूमि तथा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या 17(1)/74-एस०एस० II खंड-II(च)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 16th January, 1984

S.O. 523.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints all Sub-Divisional Officers in the various sub-divisions in the State of Orissa as Settlement Officers for the purpose of performing, in addition to his own duties as Sub-Divisional Officers within their jurisdiction, the functions assigned to a Settlement Officer by or under the said Act in respect of the land and properties forming part of the compensation pool within the State of Orissa.

[No. 17(1)/74-SS.II.(Vol.II)(F)]

का०आ० 524.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) तथा धारा 33 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग आयुक्त व सचिव, राजस्व विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर द्वारा उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त, उड़ीसा राज्य में मुआवजा पूल की भूमियों तथा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भी किया जायेगा।

[संख्या 17(1)/74-एस०एस० II(खंड-II) (ज)]

S.O. 524.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (4) of section 24 and section 33 of the said Act shall be exercisable also by the Commissioner-cum-Secretary, Revenue Department, Government of Orissa, Bhubaneswar, in addition to his own duties, in respect of lands and properties forming part of the compensation pool within the State of Orissa.

[No. 17(1)/74-SS.II.(Vol.II)(H)]

का०आ० 525.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सभी समाहर्ताओं को उनके अधिकार क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिए उड़ीसा राज्य में मुआवजा पूल की भूमि तथा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

[संख्या-17(1)/74-एस०एस० II (खंड-II) (छ)]

S.O. 525.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints all the Collectors in the State of Orissa as Settlement Commissioners for the purpose of performing, in addition to their own duties as Collectors within their jurisdiction, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the compensation pool within the State of Orissa.

[No. 17(1)/74-SS.II.(Vol.II)(G)]

का०आ० 526.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सभी तहसीलदारों को उनके तहसीलदार के अधिकार-क्षेत्र के कार्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा अभिरक्षक को सौंपे गए सभी कार्यों का करने के उद्देश्य से उड़ीसा राज्य में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के लिए सहायक अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या-17(1)/74-एस०एस० II(खंड-II)(ङ)]

S.O. 526.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints all Tehsildars in the State of Orissa, as Assistant Custodians for the purpose of discharging, in addition to their own duties as Tehsildars within their jurisdiction, all duties imposed on such Custodian by or under the said Act in respect of evacuee properties in the State of Orissa.

[No. 17(1)/74-SS. II. (Vol. II) (E)]

का०आ० 527:—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सभी कलक्टरों/अवर जिलाधीशों को उनके कलक्टरों/जिलाधीशों के अधिकार क्षेत्र के कर्तव्यों के अलावा उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से उड़ीसा राज्य में अवर अभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति नियुक्त करती है।

[संख्या-17(1)/74-एस०एस० II खंड II(ग)]

S.O. 527.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints all the Collectors/Additional District Magistrates in the State of Orissa as Additional Custodians for the purpose of discharging, in addition to their own duties as Collectors/Additional District Magistrates within their jurisdiction, all duties imposed on such Custodian by or under the said Act in respect of evacuee properties in the State of Orissa.

[No. 17(1)/74-SS. II. (Vol. II) (C)]

का०आ० 528.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उड़ीसा सरकार के राजस्व विभाग में अवर सचिव को उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए सहायक महाभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या-17(1)/74-एस०एस०-II खंड II(क)]

S.O. 528.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Administration of Evacuee Property Act 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Additional Secretary in the Revenue Department, Government of Orissa as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed by or under the said Act.

[No. 17(1)/74-SS. II. (Vol. II) (A)]

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1984

का०आ० 529.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के विभिन्न अनुमंडलों के अनुमंडलाधिकारियों को उनके अनुमंडलाधिकारी के अधिकार-क्षेत्र के कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा उपअभिरक्षक को सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करने के लिए उड़ीसा राज्य में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों के लिए उपअभिरक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या-17(1)/74-एस०एस० II खंड-II(ख)]

के०सी० गेहानी, उप सचिव

New Delhi, the 18th January, 1984

S.O. 529.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints the Sub-Divisional Officers in the various Sub-Divisions in the State of Orissa as Deputy Custodians for the purpose of discharging, in addition to their own duties as Sub Divisional Officers within their jurisdiction all duties imposed on such Deputy Custodian by or under the said Act in respect of Evacuee Property in the State of Orissa.

[No. 17(1)/74-SS. II (Vol. II) (D)]

K. C. GEHANI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1984

का०आ० 530:—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मैं इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए सहायक महाभिरक्षक निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त उड़ीसा सरकार के राजस्व विभाग में अपर सचिव को महाभिरक्षक की निम्न शक्तियां सौंपता हूँ, अर्थात् :—

(1) अधिनियम की धारा 24 तथा 27 के अधीन शक्तियां।

(2) अधिनियम की धारा 10(2)(o) के अधीन किसी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अनुमोदन की शक्तियां।

(3) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन नियमावली 1950 के नियम 30-ए के अधीन मामलों के हस्तान्तरणों की शक्तियां।

[संख्या-17(1)/74-एस०एस० II खंड II(ख)]

ए०के० मुखर्जी, महाभिरक्षक

New Delhi, the 16 January, 1984

S.O. 530.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-section (3) of section 55 of the Administration of Evacuee Property Act 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to the Additional Secretary in the Revenue Department, Government of Orissa appointed as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the State of Orissa, the following powers of the Custodian General, namely.—

(i) powers under section 24 and 27 of the Act;

(ii) powers of approval of transfer of any evacuee property under section 10(2)(o) of the Act;

(iii) powers of transfer of cases under rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules 1950).

[No. 17(1)/74-SS. II. Vol. (II) (B)]

A. K. MUKHERJEE, Custodian General

(Department of Labour)

New Delhi, the 4th February, 1984

S.O. 531.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the Life Insurance Corporation of India, Raipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 25-1-84.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(13)/1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Division Office, Raipur and their workmen represented by the General Secretary, Raipur Divisional Insurance Employees Union, Division Office of L.I.C., Phafadih, Raipur (M.P.).

APPEARANCES :

For Management—Shri H. N. Vyas, Advocate.

For Workmen—Shri P. O. Pathak, Advocate.

AWARD

Dated, the January, 18, 1984

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947) referred the following dispute regarding the transfer and reversion of Shri R. M. Kher, Cashier, in the services of the Life Insurance Corporation, for adjudication. The dispute referred is in following terms :—

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Division Office, Raipur in relation to its Branch at Bhilai, in reverting Shri R. M. Kher,, Cashier, to the post of Assistant and subsequently transferring him from Bhilai to Raipur is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The following facts would be necessary for appreciating the question relating to reversion. R. M. Kher was appointed as "Assistant" at Divisional Office Jabalpur and was confirmed on that post by an order dated 26-11-1964 with effect from 5-1-1964 on a salary of Rs. 130 p.m. in the scale of Rs. 130—5—155—6—167-8-207—10—257—12—281—EB—12—305—15—350-20—370. He was subsequently transferred to Bhilai Office in the same capacity i.e. as an Assistant with effect from 19-7-1971. Kher was allowed to officiate as Cashier from 6-7-1977 in place of Kotangale. He was selected by the Divisional Manager to work as a Cashier against vacancies in the Bhilai Branch under the existing pay scales. The Cashier at Bhilai Branch was paid special pay of Rs. 25 under an order dated 23-11-77. It appears that in the set up existing, the post of Assistant and the Cashier are in the same cadre and grade. A cashier posted to a place which carried a special allowance would always get the special allowance in addition to pay of the post. If an Assistant was required to work as a Cashier he also got this special pay of Rs. 25 when posted at Bhilai.

3. It appears that in 1969 Kher was charge-sheeted for committing some fraud. The management took a lenient view and imposed punishment of withholding one increment by order dated 12-9-1973. Kher was arrested by the police in a gambling case. He was convicted and was ordered to pay a fine of Rs. 25 or to undergo punish for seven days. The management was of the opinion that Kher had not conducted himself in a manner becoming the dignity of his office and were further of the opinion that in the interest of policy holders it was not proper to keep such a person on the post of Cashier which warranted a high degree of rectitude and integrity. Kher was, therefore, transferred to Raipur. According to the management Kher was involved in many financial irregularities at Bhilai and they were contemplating disciplinary action against him. It was, therefore, thought desirable that he should not continue to work at Bhilai and accordingly was posted at Raipur, a place nearer to Bhilai.

4. Parties to the present dispute have not led oral evidence in this case. The documents produced by the management bring out the above position stated by me in the narration of facts. That being so, one thing is qiute clear. that the transfer in the instant case was for administrative exigencies and could not be said to be vindictive or for the purposes of victimising Kher. It may also be stated that under the service conditions he was liable to be posted anywhere in India. Unions contention, however, is that Kher can only be posted to a place where he would get a special allowance otherwise there would be a loss of emoluments resulting in reduction of rank and the order would serve as a punishment on him. Being punitive it would be necessary to give him show cause notice and the procedure of department will have to be followed and it is only when he is found guilty that he could be punished. Since no departmental enquiry took place the order was against natural justice and was liable to be struck down. The only question therefore that remains to be considered is whether in the circumstances stated above a transfer to a place where no special pay was paid to the Cashier could be said to be reduction in rank or an order entailing a loss in salary which would amount to punishment If it did amount to punishment naturally the order would be bad.

5. 'Special pay' under the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations 1960 is defined as under :—

"3(k) 'Special pay' means an addition of the nature of pay to the emoluments of a post or of an employee in consideration of—

(i) the special arduous nature of duties; or

(ii) a specific addition to the work or responsibility."

It therefore appears that whenever arduous nature of duty is taken from a workman he could be compensated by a special pay in addition to the emoluments carried on the post. This is not a case falling under Clause (ii) of (k) where he had been given additional work or an added responsibility was assigned. The case would specifically fall under Clause (i) of (K) of Regulation 3 of the said Regulations. Since 'Special pay' was for duties entailing either work which was arduous or for an additional work or responsibility, it was only compensation for something done extra outside the normal. Whenever special pay was given special nature of work was extracted or an additional work or responsibility was assigned. Therefore if a person was relieved from such assignment or was not given such work he came to do the normal work of the post. Apparently if such special assignment which carried the special pay is taken away from the workman, in my opinion, there is no reduction in rank. The Regulation 57 does not come into play in the instant case. This regulation deals with reflxation of salary on an appointment to a higher grade. Now if the grade to which Kher was appointed was not higher Regulation 57 would have no application. If Kher had been appointed as Cashier at Raipur which did not carry the special pay it would not be a higher grade. It could not be a higher grade if it were appointed at Bhilai which carries a special pay. Therefore Regulation 57 being out of the way explanation (1) to Clause (2) of the Regulation 57 is not applicable. In my opinion, there is no case made out as would show that there has been a reduction in rank if the employee had been transferred to a place which did not carry special allowance. Nor could it be said that the order of transfer to Raipur entails loss of basic emoluments as could be said to be punitive or is denrivation to the workman the emoluments to which he would ordinarily be entitled.

ORDER :

Accordingly I render this award and say that the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Division Office, Raipur, in relation to its Branch at Bhilai in transferring Shri R. M. Kher to the post of Assistant at Raipur does not amount to reversion and seems wholly justified in the exigencies of the case. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer
[No. L-17012/14/80-D.IV(A)]
S. S. PRASHER, Desk Officer.

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1984

का० आ० 532.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, सी-30, फेज-2, इण्डस्ट्रीयल फोकल पाइन्ट, एस० ए० एस० नगर (मोहाली) पंजाब।

नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019 (7)/84-पी० एफ०-2]

New Delhi, the 30th January, 1984

S.O. 532.—Wehreas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Punjab Communications Ltd., C-30, Phase-II, Industrial Focal Point, S. A. S. Nagar (Mohali) Punjab have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(7)/84-P. F. II]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1984

का० आ० 533.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 44 पार्क स्ट्रीट (नवीं मंजिल) कलकत्ता-700016.

नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017 (4)/84-पी० एफ-2]

New Delhi, the 3rd February, 1984

S.O. 533.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Regional Provident Fund Co-operative Credit Society Ltd, 44, Park Street (9th Floor) Calcutta-700016, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-37017(4)/84-P. F. II]

का० आ० 534.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सरदार सर्जिकल्स, 93, दक्षिणदारी रोड, कलकत्ता-48 और समेत इसका कार्यालय 7-नालिन सिसिरकार स्ट्रीट, कलकत्ता-700004 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(3)/84-पी०एफ-2]

S.O. 534.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employers in relation to the establishment known as Messrs Sardar Surgicals, 93 Dakshindari Road, Calcutta-700048 including its office at 7-Nalin Sircar Street, Calcutta-700004, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(3)/84-P. F. II]

का० आ० 535.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, 3780, लंगर का बालाजी का रास्ता, जयपुर राजस्थान। नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि [illegible] प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(12)/84-पी० एफ-2]

S.O. 535.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Rajasthan Netrahin Kalyan Sangh, 3780, Laughar Ka Balaji Ka Rasta, Jaipur, Rajasthan, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(12)/84-P. F. II]

का० आ० 536.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इण्डस्ट्रीयल डिटेक्टिव फायर एण्ड सिक्योरिटी एजेन्सीज 'प्राइवेट' लिमिटेड, इयात्तिल लेन, चित्तूर रोड, अरनाकुलम, कोचीन-682011 अरनाकुलम गांव, कानायान्नूर तालुक, अरनाकुलम जिला, केरल। नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(11)/84-पी० एफ-2]

S.O. 536.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Industrial Detective Fire and Security Agencies Private Ltd., Iyyattil Lane, Chittoor Road, Ernakulam, Cochin-682011, Ernakulam Village, Kanayannur Taluk, Ernakulam District, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(11)/84-P. F. II]

का० आ० 537.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री भवानी फर्नीचर, पुलकेरे, मंगलौर—करकला रोड, करकला-574104, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(10)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 537.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Bhavani Furniture, Pulkere, Manglore-Karkala Road, Karkala-574014, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said estabilshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(10)/84-P. F. II]

का० आ० 538.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयपुर क्वालिटी स्वीट्स, ई-3, गोखले मार्ग "सी"-स्कीम, जयपुर, राजस्थान नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(9)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 538.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Jaipur Quality Sweets, E-3, Gokhle Marg 'C'—Scheme, Jaipur Rajasthan, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(9)/84-P. F. II]

का० आ० 539.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैनटेक कन्सलटेन्टस प्राईवेट लि०, 805, विशाल भवन 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(6)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 539.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mantec Consultants Pvt. Ltd., 805, Vishal Bhavan, 95, Nehru Place, New Delhi-110019, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellanous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(6)/84-P. F. II]

का० आ० 540:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सागे पब्लिकेशन्स प्राईवेट लि० सी-236, डीफेन्स कालोनी नई दिल्ली 110024 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(4)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 540.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sage Publications India Private Ltd., C-236, Defence Colony, New Delhi-110024, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(4)/84-P.F.II]

का० आ० 541:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रतना वेनिजया, 842, चितला गेट, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(5)/84-पी० एफ०-2]

S.O. 541.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ratna Vanijya, 842, Chitla Gate, Chawri Bazar, Delhi-110006, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(5)/84-P.F.II]

का० आ० 542:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सोना डिस्टीलरीज प्राईवेट लिमिटेड, 201-202, मत्स्य इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर, राजस्थान नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(8)/84-पी० एफ०-2]

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 542.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sona Distilleries Pvt. Limited, 201-202, Matsya Industrial Area, Alwar, Rajasthan, have appeared that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the privisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019(8)/84-P.F.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

New Delhi, the 3rd February, 1984

S.O. 543.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kooridih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st January, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 8 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kooridih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited., P.O. Sonardih, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated, the 25th January, 1984

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012-(300)/81-D.III(A) dated the 21st January, 1982, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the action of the management of Kooridih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad in not paying Category-IV wages as Cap Lamp Fitter to Shri Bisheswar Rewani is justified ? If not, to what relie is the workman concerned entitled and from what date ?"

2. The dispute has been settled out of court. A memorandum of settlement dated 25-1-1984 has been filed in court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.

[No. L-20012(300)/81-D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer.

Part of the Award.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 AT DHANBAD

Reference No. 8/82

Employers in relation to the management of Kooridih Colliery M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their Workmen

Petition of Compromise

The humble petition on behalf of the parties above named most respectfully sheweth :—

(1) That without prejudice to the contention of the parties the dispute referred by notification No. L-20012-(300)/81-D.III(A) dated 21-1-82 has been amicably settled on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

(a) That the concerned workman Shri Bisheshar Rewani will be designated as Cap Lamp fitter and will be fixed in Category-IV with initial basic starting with effect from 1-1-1983.

(b) That the concerned workman will not claim any difference of wages for the period prior to 1-1-1983.

(c) That in view of the aforesaid settlement there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and will be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

FOR THE WORKMEN : FOR THE EMPLOYERS :

(1) Sd/- illegible.
Secretary R. C. M. S.

(2) Sd/- illegible
Branch Secretary
R.C.M.S.

Sd/- Illegible
General Manager
Govindpur Area.
Sd/- Illegible
Personnel Manager
Govindpur Area.

Declaration

I, Shri Bisheshwar Rewani, the concerned workman do hereby declare and state that I have fully understood the contents of the terms of settlement explained to me in Hindi and I accept the terms of settlement with my own volition without pressure from any side.

Signature of the concerned workman.

(Bisheshwar Rewani.)

New Delhi, the 4th February, 1984

S.O. 544.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th January, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 136 of 1980

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Hoti Lal,
Part-time Sweeper,
Regional Office,
Agra.

AND

Punjab National Bank,
Agra Region,
Agra.

PRESENT :

Shri O. P. Nigam—for the workman.

Shri P. K. Goswami—for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No L-12012/187/80-D.II.A, dated 16th December, 1980 made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication.—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Agra Region, Agra in taking also the work of night guard from Shri Hoti Lal, Part-time sweeper without giving him the appropriate full time wages, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Today, the representative of the workman indicated that the claimant did not want to proceed with the claim and was not interested in pursuing the reference. A written request made by Shri Hoti Lal, concerned workman, attested by Shri D. S. Sodhi, State President of P.N.B.E.U. has also been submitted by him to that effect.

3. I am satisfied that the workman is no longer interested in pursuing the reference made to this Tribunal and, therefore, a 'No Dispute Award' is made.
January, 17, 1984.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

January 17, 1984.

O. P. SINGLA, Presiding Officer.

[No L-12012/187/79-D.II.A]

N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 4th February, 1984

S.O. 545.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bolani Ores Mines of Durgapur Steel plant of SAIL District Keonjhar and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st January, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference No. 38 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bolani Ores Mines of Durgapur Steel Plant of SAIL. P.O. Bolani, Dist. Keonjhar;

AND

Their Workman

PRESENT :

Justice M. P. Singh—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. S. K. Dutt, Advocate.
On behalf of Workman —Absent.

STATE : Orissa. INDUSTRY : Ores Mines

AWARD

By Order No. L-26011/2/82-D.III(B) dated 27-5-1983,. Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour referred the following dispute for adjudication :

"Whether the termination of service of Shri Dannis Everson, Mazdoor of Bolani Iron Ore Mines of SAIL, Bolani with effect from 12-8-81 is justified? If not, to what relief he is entitled to ?"

2 In my opinion the termination of service of Dannis Everson is justified. MW-1 S. K. Mukherjee the Dy. Manager Personnel has deposed that Dannis Everson started absenting from his duty since 4th July 1981 without intimating or taking permission. He has proved a letter Ext. M-1 dated 12th August 1981 sent by the management to the concerned workman. The letter states that D. Everson had lost lien on his appointment with immediate effect because in the opinion of the management he was not interested in his employment. The management thought so due to his unauthorised absence since 4th July 1981. The witness has proved another letter Ext. M-2 dated 17 December 1981 written by the management to the ALC(C), Rourkela (Orissa). In this letter also it is clearly stated that Everson had remained absent for more than 30 days and had started absenting since 4th July 1981 unauthorisedly and as such the management came to the conclusion that he was not interested in his present employment. I think the stand taken by the management in these two letters (Ext. M-1 and M-2) is correct. Even the Barbil Workers' Union who raised this dispute stated in their application for adjournment for six months dated 14.8.1983 that Dannis Everson was absconding and was untraceable. This clearly shows that the concerned workman has abandonde his service. The union has not appeared on any date fixed in the case. They have not taken any effective steps to proceed with the case. In these circumstances it is reasonable to infer that the union is also not interested in the progress of the case. The case has been heard exparte and I do not see any good ground to reject the prayer of the management to pass a no dispute award. It is to be noticed that even uptoday nobody knows the whereabouts of the concerned workman. The union has mentioned in their petition for adjournment on 14 August 1983 that the whereabouts of Everson are not known and that the concerned workman had abandonded. The word 'absconded' in the union's letter is significant. It may mean that the concerned workman after committing some serious offence has absconded. Any way the facts and circumstances aforesaid lead me to the conclusion that the concerned workman has abandoned service and so he has disappeared It is a case, I think, of voluntary abandonment of service and not of retrenchment. In such a situation it must be held that the union is no longer interested in the dispute.

3. In the result, let a no dispute award be passed. This is my award.

Dated, Calcutta.
The 19th January, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-26011/2/82-D.III(B)]

NAND LAL, Desk Officer.

New Delhi, the 3rd February, 1984

S.O. 546.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by S/Shri Jahan Mia and Surath Roy, Surface Trammer of Lower Kinda Colliery against the management of Lower Kenda Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Baula, Dist. Burdwan.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Complaint Case No. 5/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Jahan Mia, Surface Trammer and Surath Roy, Surface Trammer of Lower Kenda Colliery—Complainants

Vs.

The Agent, Lower Kenda Colliery,
M/s. Eastern Coalfields Ltd.
P.O. Baula, Dist. Burdwan—Opp. Party

APPEARANCES :

For the Complainants—Sri S. Yar Mohammad, Org. Secy., C.M.S.

For the Opp. Party—Sri N. Das, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal

Dated, the 6the January, 1984

AWARD

This is a Complaint Petition U/s. 33-A of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 filed by Julian Mia and Surath Roy, Surface Trammer of Lower Kenda Colliery.

2. The case of the workmen is that they have been stopped from going to their duties on and from 1-8-82 and 16-9-82 respectively on the pretext that they had been superannuated on attaining the age of superannuation. It is submitted that the opp. party has got a fictitious and concocted Form B register increasing the age of workmen with a purpose to retire them earlier. It is also stated that a Reference Case No 33/82 is pending before this very Tribunal for the same issue and hence the termination is illegal.

3. The defence of the management is that the present complaint petition is not maintainable as the complainants have no concern in the dispute which is a subject matter of Reference No. 33/82 pending before this Tribunal and no provision of Section 33 of the Industrial Disputes Act has been violated in this case. It is submitted that the present petition is not maintainable and hence it should be dismissed.

4. The point for consideration is as to whether the action of the management is legal and valid.

5. It will be seen that the Reference Case No. 33/82 is with regard to the justification of the management in superannuating one Sri Chand Majhi with effect from 1-8-81. The said case was regarding superannuation of a particular workman in which the concerned complainants can in no way be connected with that dispute. Further Section 33 of the I.D. Act do not cover the case of superannuation. The concerned workmen were superannuated on attaining the age of superannuation and if they had any grievance they should have raised an industrial dispute and get a Reference made U|s 10 of the I.D. Act. There is nothing to show that there has been any violation by the management of any of the provisions of Section 33 of the I.D. Act, The Reference case in question relates to an individual dispute with which the concerned workmen were in no way connected.

6. Considering these, I hold that the present complaint petition is not maintainable. It is dismissed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-19014(2)/83-D.IV(B)]

C. D. BHARDWAJ, Desk Officer.

New Delhi, the 10th February, 1984

S.O. 547.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board Jammu and their workmen, which was received by the Central Government on 19th January, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 141/83

PARTIES :

Employers in relation to the management of Cantonment Board Jammu.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. C. Sharma.

For the Workman—None.

CANTONMENT BOARD JAMMU (J&K)

AWARD

Dated the 11th of January, 1984

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide their Order No. L-13011(4)/82-D.II(B) dated the 24th of September, 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Cantonment Board Jammu in not treating the period of absence of its Safaiwallas from 1st September, 1982 to Half day of 2nd September, 1982 as leave or duty but treating that period as break in service is justified ? If not, to what relief are these Safaiwallas entitled ?"

2. Today when the case came up for hearing, the parties reported a settlement and filed an attested copy of resolution No. 12 dated 30th October, 1983 passed by the Cantonment Boahd Jammu. According to the terms of the settlement the Board have already revoked thte impugned order except that, its effect would continue in so far as the facility of Leave and Leave Travel Concessions are concerned.

3. In my considered opinion the terms of settlement are fair to the parties and in particular to the Workmen because it saves them from the consequences of break in service, in serious matters like Gratuity and Pension etc. I, accordingly, return a No-dispute Award.

Chandigarh,
11-1-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-13011(4)|82-D.II(B)]
T. B. SITARAMAN, Undre Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984